[श्रीमती कृष्णा साही]

सभापति महोदय, पंजाब में 45 रुपये रोज भत्ता मिलता है । इस के अलावा गाड़ी खरीदने के लिये . . .

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पाखण्ड पूरा आप लोग रचाये हुए हैं, कोई सिद्धान्त की बात करे तो वह पाखण्डी हो गया, यह कहां से सीख लिया है । आप अपनी बात रखिये ।

श्रीमती कृष्णा साही : 45 हजार रुपया पंजाब में मकान बनाने के लिए लोन दिया जाता है और गाड़ी खरीदने के लिये भी 30 हजार रुपया लोन दिया जाता है । हरियाणा में भी यही बात है और वहां पर भी गाड़ी खरीदने के लिए 30 हजार रुपया लोन दिया जाता है । राजस्थान में, सिक्किम में और तामिलनाडु आदि कई जगहों पर मकान रहने के लिए फ्री दिया जाता है लेकिन हमारे यहां मकान का भी किराया लगता है । मकानों की हालत खराब है और जनता में यह भ्रम फैला हुआ है कि मेम्बरों को रहने के लिए मकान फ्री दिया जाता है, टेलीफोन फ्री मिलता है, बिजली फ्री मिलती है और पानी फ्री मिलता है । मेरा कहना यह है कि जनता के बीच में यह भ्रम फैला हुआ है कि हम लोग शान व शौकत से रहते हैं और हमारा इन चीजों पर कोई खर्च नहीं होता है । मेरा एक प्रस्ताव भी इस के बारे में था और इन की भावनाओं की कद्र करते हुए, मैं यह कहना चाहती हूं कि वर्त्तमान सेक्रेटेरिएट सुविधा या पैसों से क्या होगा । आप एक एसिसटेंट 500 रुपये में नहीं रख सकते हैं, एक स्टेनोग्राफर नहीं रख सकते हैं । स्थिति यह है कि सुबह से ले कर 11 बजे तक जब तक हम पार्लियामेंट हाउस आते हैं, हर 5 मिनट के बाद घंटी बजती है और अगर हम बाथरूम में भी होते हैं या पूजा करते रहते हैं तो हमें बाहर दौड़ कर देखना होता है कि कौन कौन है या फिर जो हमारे घर में रहते हैं, वे देखते हैं लेकिन वे कितने हैं । छोटा नौकर अगर है, तो वह कितना क्या कर सकता है ।

दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि हमारा पोस्टल स्टेम्पस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है । 8 लाख से 10 लाख का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, 6 विधान सभाओं या 5 विधान सभाओं को मिला कर हम प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन उस के लिए हमें बहुत कम पैसा मिलता है । इसके अलावा मेरा यह कहना है कि विधान सभा में एक मेम्बर को 15 हजार टेलीफोन काल फ्री हैं और हम को भी 15 हजार टेलीफोन काल फ्री हैं । अगर 6 विधान सभाओं का हिसाब हम लगाएं, तो उसके अनुपात में हम को बहुत कम टेलीफोन काल फ्री है । हमारे बच्चे हमको पहचानते नहीं क्योंकि हमें खानाबदोशों की तरह से जिन्दगी बितानी होती है । इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि अगर पति और पत्नी साथ चलते हैं और अगर किसी का पति या पत्नी नहीं है और उसके साथ कोई सहयात्री जाता है, तो उसको फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए । अब होता क्या है कि खुद तो फर्स्ट क्लास में बैठा है । और दूसरा सैकेन्ड क्लास में बैठा है । अब पत्नी कोई गठरी तो है नहीं कि सेशन के टाइम पर लाकर रख दी और सेशन के बाद फिर ले कर चले गये । वह कोई मोटर तो है नहीं कि जहां चाहा रख दिया । इसलिए मेरा कहना यह है कि पति या पत्नी या सहयात्री अगर साथ जाते हैं, तो उनको फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए । हमारे एक बहुत बुजुर्ग बिहार के सदस्य थे बेचारे । उनकी मृत्यु हो गई और 10-15 स्टेशन के बाद जा कर किसी को पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई । मैं बहुत अदब से कहना चाहती हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस के लिए आप घबड़ाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेगी कि हमने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली । सबसे बड़ी बात यह है कि एक संसद सदस्य की जो जिम्मेवारी होती है, कम से कम उस जिम्मेदारी को वहन करने लायक हम को मिलना चाहिए । 30-40 लोग हमारे यहां रोज आते हैं और उन को चाय पिलानी होती है । शास्त्री जी तो चीनी खाते नहीं इसलिए उनको चीनी की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप यह कैसे कहती हैं, मैं 6-7 आदमियों को रोज चाय पिलाता हूं ।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं यह कहती हूं कि एक तरफ तो ये हमारे मंत्री जी को

कहते हैं कि हम को आप फैसेलिटीज नहीं देते और दूसरी तरफ सिद्धान्त की बात करते हैं । इन की कथनी और करनी में फर्क है और यह फर्क नहीं होना चाहिए । जो कथनी और करनी में फर्क करते हैं, वही सिद्धान्त की बात करते हैं । हम लोग सिद्धान्त की बात सही जगह पर करते हैं । इसमें इतनी वित्तीय इन्वोल्वमेंट की बात नहीं है । इसलिए मेरा यह अनुरोध होगा कि जहां फ्री हाउस की बात होती है, उसके बारे में सोचा जाए । आन्ध्र प्रदेश में फ्री मकान दिया जाता है और जैसा मैंने सुना है मद्रास में यूटेंसिल्स और लीनन सब फ्री मिलता है।

एक बात और कहना चाहती हूं कि विधान सभा के सदस्य हमको चिट्ठी लिख देते हैं कि इतने आदमी आ रहे हैं, इनकी देखरेख करना । अगर उनकी देखरेख नहीं होती है, तो फिर वोट के समय वे याद रखते हैं, एम. एल. ए. से लेकर जनता तक कि हम वहां गये और हमें एक पियाली चाय भी नहीं पिलाई गई । मैं परसों की बात करती हूं रात को साढ़े 11 बजे हमारे क्षेत्र से 25-30 आदमी हमारे यहां आ गये । एक तो हम महिला हैं । हमारे भाई लोगों को शायद कुछ कम परेशानी होती होगी । एक महिला होने के नाते हमें अधिक परेशानी होती है । जिस ट्रेन से वे आये थे, वह ट्रेन लेट थी । बिचारे मर्द, औरत, बच्चे थे, सभी हमारे यहां आये और उन लोगों को हमें ठहराना ही होता है क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधित्व तो करती हूं ।

हम लोगों को जो मकान मिले हैं उसका पर्याप्त किराया लिया जाता है । फर्नीचर के लिए पांच हजार की सीलिंग लगा रखी है कि इस से ज्यादा फर्नीचर हमको नहीं मिल सकता है उससे ज्यादा का किराया काफी देना पड़ता है । डोर मेट जो हम लेते हैं उनका हमें दो रुपये महीने किराया देना पड़ता है । हमें दो तरह का फर्नीचर मिलता है एक मूवबल और दूसरा नान मूवेबल हमारे यहां राइटिंग ब्यूरो होता है, उसका भी हम से किराया चार्ज किया जाता है । वह दीवार के साथ लगा हुआ है लेकिन उसको भी मूवेबल माना जाता है । इस के अलावा हमारे यहां जमादार, मेहतर आता है, उसको अलग देना पड़ता है । इस तरह से बहुत से हमारे एडीशनल खर्च हो जाते हैं ।

ड्राइंग रूम में जो राइटिंग ब्यूरो फिक्स है पता नहीं उसको आप कैसे मूवेबल मानते हैं । वह दरवाजे से बाहर निकल नहीं सकता है लेकिन उसको भी मूवेबल मान कर उसका किराया चार्ज किया जाता है । ऐसी बहुत-सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें देखना है ।

ये सारी बातें कहने का मेरा मतलब यही है कि आप स्टेण्डर्ड आफ लीविंग की बात को और सुविधाओं की बात को छोड़ दीजिए लेकिन हमारे जो उत्तरदायित्व हैं उनके निर्वहन के लिए तो हमें आवश्यक साधन प्रदान कीजिए, बेशक हमें आप सुखसुविधाएं न दें । हमें इतना तो दीजिये कि हमारे यहां तनावपूर्ण वातावरण न रहे । हमारी जिन्दगी एक खानाबदोश की सी जिन्दगी होती है। घर में न पति पत्नी को देखे, बच्चे मां को या पिता को न देखे और इस प्रकार से हमारी जिन्दगी तनावपूर्ण बनी रहे । इस से निकालने के लिए भी और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए, उनका अच्छा प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें उचित सुविधाएं तो प्राप्त होनी ही चाहिए । चाहे मंत्री हों, चाहे सदस्यगण हों, उनकी सुविधाएं आजकल बहुत कम हैं । इन से हमारा दिन-रात का काम नहीं चल सकता है । हमें दिन-रात काम करना पड़ता है । इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस बिल को पास करना जरूरी है । मैं सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि इस को सर्वसम्मति से पारित करें ।

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): Mr. Chairman, Sir, the hon. Members have pointed out that if we say that salary and allowances should not be increased, it would be a hypocrisy. I think, those hon. Members who call us hypocrites, most probably live in a high society. They have never gone to the villages; they have never seen the plight of villagers.

It is a fact that the prices have been increasing. But the Government has been pleading with us that they have succeeded in arresting the price

[Shri Sudhir Giri]

rise. It is a member of the ruling party who has pointed out that the prices have been increasing day by day.

17.00 hrs.

It is a fact that prices have been increasing but we should keep in mind the fact that we are the representatives of the people, who live in the villages and in the basti areas of the towns and cities. We know very well how much suffering they have to undergo during these price-spiralling days and the Planning Commission has pointed out in its report that more than 50 per cent of the people, most probably 50.6 per cent of the total population, live below the poverty line. But our assesmsent in this respect is that more than 70 per cent of the people in India live below the poverty line. Most probably, many Members who adorn this august House are not fully aware of the lives of the villagers who live even a beastly life. I say so because in a hut boys and girls and husband and wife and cows and buffaloes and goats and sheep live together side by side. There is no difference between the beasts and the human beings.

A demand has been made for payment of Rs. 65/- during the session period. But, you must remember that even an average family in the villages cannot earn Rs. 50/- per month. Most probably, many of our Members do not know this fact.

The increase in salaries and allowances has been justified on the ground that efficiency should be maintained. But, to maintain the efficiency of the hon. Members I would suggest to the Government that Stenographers or typists should be provided to them when they need and if we do this, our efficiency can be maintained and we can act as Members of Parliament efficiently. With these words I oppose the Bill.

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : सभापति जी, मोहतरम डागा साहब ने सेलरी एण्ड अलाउंसेस बढ़ाने के बारे में जो बिल प्रस्तुत किया है, उस बिल का मैं समर्थन करते हुए चंद बातें कहना चाहता हूं ।

जैसा कि डागा साहब ने इस एवान के सामने डिटेल में इस मसले को पूरी तरह उभारा, कोई टापिक उन्होंने छोड़ा नहीं है, जिस पर मैं और कुछ कह सकूं । लिहाजा उन बातों पर मैं न जाते हुए चन्द प्वाइंट आपके नोटिस में लाना चाहता हूं जो कि शायद बहुत सारे सदस्यों के जहन में नहीं होंगे । खासतौर पर उन इलाकों के बारे में जो ट्राइबल हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं या जो रेगिस्तानी इलाके हैं—जैसे राजस्थान है, और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वहां पर क्या-क्या मुश्किलात मेंबरों को भुगतनी पड़ती है, उन मुश्किलात को देखते हुए डागा साहब ने अपने बिल में मेम्बरों की तनखाह जो 500 रुपये के बजाए एक हजार रुपया बढ़ाने के लिए और अलाउंसेस 51 रुपये के बजाए 101 रुपये करने के लिए कहा है, मैं समझता हूं कि किसी हद तक वह भी कम होगा । उन हालात का सही ढंग से जायजा लिया जाए, जिन हालत में ट्राइबल्स एरिया में और पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों के पास मेंबर्स को जाना पड़ता है । जहां तक रेलवे पास का सम्बन्ध है स्पाउज के लिए भी फ्री फर्स्ट क्लास पास की बात इस बिल में कही गई है । यह ठीक बात है । वह मिलना चाहिये । लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन की कन्स्टीच्यून्सी में रेलवे लाइनें हैं नहीं है । बहुत से ऐसे आनरेबल मेम्बर्ज हैं जिन के इलाकों में रेलवे का जाल बिछा हुआ है लेकिन बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहां रेलवेज ही नहीं हैं। वहां पर यह फ्री रेलवे पास की बात बेमानी बन जाती है । फ्री रेलवे पास पर आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि आप भूखे तो घूम नहीं सकते हैं । जेब में भी कुछ होना चाहिए । मैं समझता